Title: Government business during the week commencing 24th April, 2000.

13.01 hours

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN):

With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing 24th April, 2000 will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Consideration and passing of the following Bills as passed by Rajya Sabha:-

i. The Food Corporations (Amendment) Bill, 2000;

ii. The Sugarcane Control (Additional Powers) Repeal Bill, 2000.

1. Consideration and passing of the Indian companies (Foreign Interests) and the Companies (Temporary Restrictions on Dividends) Repeal Bill, 2000.

2. Further discussion on Motion of Thanks on President's Address.

3. Discussion and Voting on Demands for Grants of the following Ministries:-

i. Ministry of Communications;

ii. Ministry of Home Affairs.

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय को जोड़ा जाये:-

केन्द्रीय लोक निर्माण, सूचना एवं प्रसारण विभाग, एम.टी.एन.एल आदि विभाग में जूनियर अभियन्ता के वेतन दर को रुपये 5500 से और 6500 से शुरू किया जाता है जबकि रेलवे विभाग अभी तक जूनियर अभियन्ता के वेतन को 5000 रुपये से ही शुरू किया जाता है। इसके बारे में न्यायोचित कदम उठाकर इस वेतन दर को 6500 से शुरू कराया जाये।

डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को जोड़ा जाये:-

सरकार ने हाल ही में आर्थिक दृष्टि से कठोर कदम उठाये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अब गरीब को गेहूं 2.50 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 4.30 रुपये प्रति किलो, 10 किलो की जगह 20 किलो मिलेगा और गैर गरीब को 6.82 रुपये प्रति किलो के बजाय 9 रुपये प्रति किलो हो गया है। परिवार में 5 सदस्यों की कल्पना सरकार ने की भी है, जिसे प्रति व्यक्ति एक समय 100 ग्राम गेहूं, दिन में 200 और परिवार को एक किलो एक दिन में और माह में तीस किलो भरण पोषण के लिये अवश्य चाहिए।

मेरा आग्रह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था पर नये सिरे से विचार किया जाए ताकि गरीब को तो राहत मिल जाये।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाये:-

1. देश की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के विगत बीसियों वर्षों से नियमित छपने वाले तथा रजिस्ट्रार भारत के समाचार पत्र के यहां पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक समाचार प्रकाशित करने वाले साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्र-पत्रिकाओं को सरकार द्वारा अभी हाल ही में जारी किये गये अनुदेशों के अन्तर्गत डाक पंजीकरण के नवीकरण करने से इंकार कर दिया गया जिससे देश के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संगठनों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है। अतः इस असुविधा एवं असंतोष को समाप्त करने हेतु पूर्वतः डाक पंजीकरण के नवीकरण की आवश्यकता ।

2. सैनिक भर्ती के लिए प्रसिद्धि प्राप्त, स्वाधीनता सेनानियों की कर्मस्थली रहे तथा राजस्थान के बीचों-बीच स्थित ऐतिहासिक एवं सैनिक महत्व के अजमेर नगर में अंग्रेजों के समय से स्थापित और 1998 तक कार्यरत सेना के क्षेत्रीय भर्ती दफ्तर (जोनल रिक्रूटमेंट औफिस) को बंद कर दे

ने से घोर असंतोष व्याप्त है। अतः अजमेर नगर में सेना के क्षेत्रीय भर्ती दफ्तर को पुनः प्रारम्भ करने की आवश्यकता ।

उपाध्यक्ष महोदयः आपने जो प्वाइंट लिख कर दिए हैं, उसे ही पढ़ें। पूरा मैटर नहीं पढ़ें।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले(मालेगांव) : मेरा मैटर ज्यादा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदयः वह चाहे कम हो लेकिन प्वाइंट ही पढ़ें।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के नासिक में 2003 में महाकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है जो देवलाली, नासिक रोड, त्रम्ब, ब्रुश्वर और नासिक से संबंधित है। इसमें लाखों-लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। अतः यहां की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होनी चाहिए। साथ ही यात्रियों, पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, उसका उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए।

मालेगांव, भिवंडी शहर में ज्यादा से ज्यादा पावरलूम हैं। इसके ऊपर लाखों मजदूर निर्भर करते हैं लेकिन सूत के दाम अभी बढ़े हैं, बिजली के भी दाम बढ़ गए हैं और गोडाउन की अच्छी तरह से सुविधा नहीं है। इसलिए यह धंधा संकट में आया। इस संकट का समाधान करने के लिए तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिए।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, following item may be included in the next week's agenda:-

The price hike of food grains have adversely affected the Public Distribution System in India, particularly in Kerala State.

Sir, day before yesterday, the Chief Minister of Kerala led an all-party delegation to the capital. They were forced to sit on *dharna* in front of the Parliament. The all-party delegation also met the Prime Minister and apprised him of the situation...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Radhakrishnan, this matter has already been listed. You have to read the text only.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Sir, as per the decision of the Central Government, after withdrawing subsidy, the position has become very serious in my State as well as in Southern States. The subsidy given on kerosene has been withdrawn and this has led the poor man to so much of difficulty. Subsidy given on rice and other food materials has been withdrawn. So, I demand the Central Government to roll back the prices. The rise in the prices of food grains has adversely affected the Public Distribution System in India, particularly in Kerala.

This item may be included in the next week's agenda as it has been a very important matter since India attained Independence.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only the approved text should be given to the Members hereafter.

SHRI KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Sir, the following item may be included in the next week's agenda:-

Volatility and crash in stock exchanges -- crisis in Capital market.

श्री विजय गोयल(चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन अफसरों पर भ्रटाचार के मुकदमे चल रहे हैं उन्हें अविलम्ब निलम्बित किया जाए। नौकरशाही की जवाबदेही बढ़ानी चाहिए। उन्हें किसी पद पर नियुक्त करने पर हर वर्ा सम्पत्ति की घोाणा के लिए कहना चाहिए। इससे सरकार के काम में पारदर्शिता आएगी।

दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए सरकार तुरन्त कदम उठाए। तब तक विभिन्न निकायों को समाप्त कर एक निकाय बनाया जाए।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सतना जिले की बाण सागर अन्तर्राज्जीय सिंचाई योजना को यथाशीघ्र पूरा कराने के लिए चर्चा की आवश्यकता है। यह योजना सन् 1984 में पूर्ण होनी थी। यह 600 करोड़ रुपए की योजना थी जो अब 3200 करोड़ रुपए की हो गई है। यह 22 वर्ा बाद भी अधूरी पड़ी है। इससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यों की सिंचाई प्रस्तावित है।

SHRI THIRUNAVUKARASU (PUDUKKOTTAI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the following items may be included in the next week's agenda.

1. Need to set up industries in Pudukkottai in Tamil Nadu as it is a backward area. Moreover, adequate land and other infrastrctural facilities are available.

2. Need to reopen closed textile mills and revive sick units in Tamil Nadu which has affected employment opportunities of lakhs of people. The problems of textile industry are due to hike in import duty of yarn and in excise duty.